गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 043
दि. 12.06.2026, शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सबसे लंबे समय तक पीएम बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड बनाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से दी गई बधाई पर धन्यवाद देते हुए मैसेज शेयर किया है.

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ करने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद देते हुए मैसेज शेयर किया है. उन्होंने कहा,

आपकी शुभकामनाओं के लिए थैंक्यू. आपके साथ मिलकर मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं.

ट्रंप ने मोदी को दी थी बधाई

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, 'मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई. वह एक प्रभावशाली नेता हैं.' उन्होंने कहा, 'मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान नेता हैं और आने वाले वर्षों में भी उनके नेतृत्व में अनेक बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं हासिल होंगी.'

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को कहा 'थैंक्यू'

इस संदेश का जवाब देते हुए मोदी ने 'एक्स' पर कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं, ताकि हमारे दोनों देशों और पूरी दुनिया को इसका लाभ मिल सके.'

पीएम मोदी ने बनाया ये रिकॉर्ड

नरेंद्र मोदी ने बुधवार (10 जून) को 4,399 दिनों के लगातार कार्यकाल के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया. उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

दुनिया के कई नेताओं ने दी बधाई

दुनिया के कई नेताओं ने उन्हें निर्वाचित होकर भारत के प्रधानमंत्री पद पर लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने के लिए बधाई दी. यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट के जरिये प्रधानमंत्री को इस कीर्तिमान के लिए बधाई दी.

12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाणः प्रधानमंत्री मोदी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7 दशमलव 7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण, तीन तलाक के खिलाफ कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और वन रैंक वन पेंशन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय हित में लिए हैं और भविष्य में भी ऐसे साहसिक निर्णय जारी रहेंगे।

इससे पहले, एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत-2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई।

इतिहास रचेंगे पीएम मोदी! पहली बार स्लोवाकिया पहुंचेगा कोई भारतीय प्रधानमंत्री, डिफेंस और निवेश पर फोकस

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक गणराज्य की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बताया कि 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। इस दौरे को भारत और स्लोवाकिया के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

व्यापार, निवेश और नई तकनीक पर फोकस

सिबी जॉर्ज के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इसके अलावा वह वहां के प्रमुख उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने तथा परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, उभरती टेक्नोलॉजी और रक्षा उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत बनाने पर विशेष जोर रहेगा।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के दौरान स्लोवाकिया ने भारत को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। इसके अलावा स्लोवाकिया ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (कल्र्ष्-एव ऋळअ) को आगे बढ़ाने में भी सकारात्मक भूमिका निभाई है। स्लोवाकिया ने एफटीए के सफल क्रियान्वयन का स्वागत किया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पश्चिम एशिया के हालात पर भी होगी चर्चा

सिबी जॉर्ज ने संकेत दिए कि प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाक नेतृत्व के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात, वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और आपसी हितों से जुड़े मुद्दे वार्ता का हिस्सा बन सकते हैं। भारत का मानना है कि इस यात्रा से न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि यूरोप के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सबसे लंबे कार्यकाल को लेकर दी बधाई

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए पोस्ट किया, " सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की।" सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, "145 करोड़ भारतीयों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूर्ण समर्पित तथा 'अमृतकाल' के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई।"

उन्होंने कहा, "भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व पड़ाव पूरे राष्ट्र के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है।

पीएम मोदी किस बात के लिए ट्रंप को थैंक्यू कह रहे हैं?' अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत पर भड़के केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहने पर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने मोदी के ट्रंप को धन्यवाद कहने पर सवाल उठाया भारतीय नागरिकों की जान जाने के बाद धन्यवाद पर आपत्ति केजरीवाल बोले, भारत को मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहने पर ह्वआपह्व के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है।

उनका कहना है कि जब भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है, तो प्रधानमंत्री आखिर डोनाल्ड ट्रंप को

किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं?

केजरीवाल ने एक्स पर साधा पीएम पर निशाना

केजरीवाल ने एक्स पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को धन्यवाद कह रहे हैं। आखिर किस बात के लिए धन्यवाद? उन जहाजों पर हमला करने के लिए जिन पर भारतीय सवार थे और भारतीय नागरिकों की जान लेने के लिए? अब यह स्थिति हमारे देश के लिए बेहद शर्मनाक हो चुकी है।

केजरीवाल ने आगे कहा, मोदी जी ने भारत की संप्रभुता, गौरव और अपने नागरिकों की जान पूरी तरह से ट्रंप के हवाले कर दी है। भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। ट्रंप को हमारे देश और हमारे लोगों के साथ अपनी मनमानी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती।

लंबित तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के दोहन से जुड़ा सालों पुराना विवाद सुलझा! 50-50 पर बनी सहमति, अमित शाह बोले-बदलेगा पूर्वोत्तर

(जीएनएस)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 11 जून को भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) को पूर्वोत्तर भारत के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

इस समझौते के जरिए दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के दोहन से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है।

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक या आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और विकसित पूर्वोत्तर के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है।

समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान अमित शाह ने कहा कि आज का दिन पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित कई जटिल मुद्दों को बातचीत और सहयोग के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया है और यह समझौता उसी का परिणाम है। गृह मंत्री ने कहा कि इस पहल से तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन की संभावनाओं को नई गति मिलेगी। साथ ही, इससे भविष्य में खनिज संसाधनों के दोहन और खनन गतिविधियों के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे।'

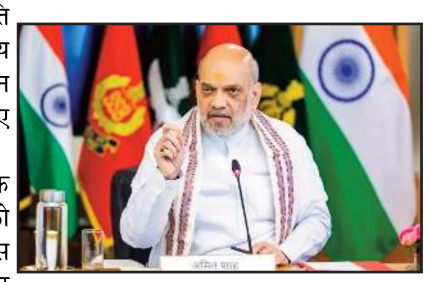

अमित शाह ने बताया कि दोनों राज्यों ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए तेल और गैस संसाधनों के उपयोग को लेकर 50-50 हिस्सेदारी के मॉडल पर सहमति बनाई है। उन्होंने कहा कि असम और नागालैंड दोनों ने यह समझा कि सीमावर्ती विवादों या अन्य प्रशासनिक चुनौतियों को देश की प्राकृतिक संपदा के उपयोग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। इसी सोच के तहत दोनों राज्यों ने साझा लाभ के सिद्धांत को अपनाया। गृह मंत्री के अनुसार, यह केवल आर्थिक समझौता नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने नागालैंड के मुख्यमंत्री का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केवल छह तेल क्षेत्रों तक सीमित रहने के बजाय पूरे नागालैंड में तेल और गैस अन्वेषण के लिए सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि नागालैंड सरकार की यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित कर सकती है। गृह मंत्री ने इसके लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका सहयोग और दूरदर्शिता इस समझौते को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन बढ़ने से न केवल राज्यों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा, तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत संरचना, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ने की संभावना है।

भारत सरकार, असम और नागालैंड के बीच हुए इस त्रिपक्षीय समझौते को पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि यह समझौता आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत को आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जिन क्षेत्रों में भूमि के मालिकाना हक को लेकर अभी भी पूरी तरह अस्पष्टता है, वहां से होने वाली कमाई को एक 'एस्क्रो अकाउंट' में सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि उसका अंतिम कानूनी समाधान नहीं हो जाता।

कॉकरोच जनता पार्टी ने पुणे में दोहराई मांगे, सीएम योगी की पुलिस ने दीपके का प्लान किया फुस्स! क्या करेंगे?

(जीएनएस)।

कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों सोशल मीडिया से सड़क तक की यात्रा कर रही है। 11 जून 2026 को पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में सैकड़ों युवाओं की भारी भीड़ ने शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद की।

वहीं, लखनऊ में 12 से 18 जून तक प्रस्तावित धरने की अनुमति पुलिस ने निरस्त कर दी। अब सवाल यह है कि अभिजीत दीपके अब क्या करेंगे? क्या यह आंदोलन रुक जाएगा या नया रूप लेगा?

11 जून को पुणे में CJP का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर में अभिजीत दीपके और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर, तख्तियां और बैनर लेकर 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' के नारे लगाए।

मुख्य मांगें :, NEET और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक रोकना, परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करना, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता, परीक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, छात्रों की समस्याओं (देरी, अनियमितताएं, मानसिक तनाव) का समाधान

दीपके ने पुणे की 'अद्भुत उपस्थिति' के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पूरा पुणे एकजुट हो गया है। चाहे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, तिलचट्टे आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और युवाओं, छात्रों तथा अभिभावकों की अच्छी भागीदारी देखी गई। उखढ ने इसे शिक्षा व्यवस्था में सड़ चुकी सड़न के खिलाफ जन-आक्रोश का प्रतीक बताया।

लखनऊ में झटकाः परमिशन क्यों रद्द हुई?

पुणे के एक दिन बाद, यानी 12 जून से लखनऊ के इको गार्डन में 12 से 18 जून तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना प्रस्तावित था। आवेदन पार्टी प्रतिनिधि विवेक कुमार की ओर से दिया गया था।

लखनऊ पुलिस से दीपके को झटका!

आयोजकों से संपर्क करने और वार्ता के कई प्रयास किए गए। कोई जवाब या समन्वय नहीं मिला। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर अनुमति निरस्त। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर अपील की थी, लेकिन पुलिस के अनुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। यह उखढ के लिए पहला बड़ा प्रशासनिक झटका है।

उखढ की शुरूआत और उभारः 15 मई से अब तक

अभिजीत दीपके (उम्र 30 वर्ष) महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है।

लखनऊ बनेगा नो ट्रिपिंग जोन, केंद्र की हेल्प से होगा आधुनिकीकरण

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने लखनऊ नो ट्रिपिंग जोन बनाने की ठान ली है। इसमें केंद्र सरकार की मदद से आधुनिकीकरण का काम होगा। इससे लखनऊ की बिजली व्यवस्था को वर्ष 2032 के हिसाब से आधुनिक किया जाएगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इसकी तैयारी में जुट गया है।

राजधानी की बिजली व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ष 2032 के हिसाब से तैयार करने की तैयारी है। इस पूरे काम को वर्ष 2028 मध्य तक करना होगा। वर्ष 2032 में राजधानी के उपभोक्ताओं को कितनी बिजली चाहिए होगी, कितने उपभोक्ता होंगे और इन्फ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत करना होगा। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम तीन सदस्यीय कमेटी करेगी।

पंद्रह सौ करोड़ रुपये खर्च करके वर्ष 2028 मध्य तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। टीम देखेगी कि कैसे पांच वर्ष में बिजली की डिमांड लखनऊ में बढ़ी है। उसी आधार पर

आगे की रणनीति बनाएगी। वर्ष 2032 में कितने बिजली उपकेंद्र व ट्रांसमिशन उपकेंद्र चाहिए होंगे।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) राजधानी में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें पावर कारपोरेशन के निदेशक होंगे, मध्यांचल के निदेशक तकनीकी और लेसा के एक मुख्य अभियंता को रखा गया है। यह समिति दीपावली तक पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट शक्ति भवन को सौंप देगी। इसके बाद मध्यांचल लखनऊ में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर काम करेगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

हर वर्ष बढ़ रही है डिमांड और उपभोक्ता

लखनऊ में हर वर्ष दो से ढाई सौ मेगावाट एम्पियर बिजली की डिमांड बढ़ रही है। हर वर्ष दो सौ मेगावाट की खपत और एक लाख उपभोक्ता बढ़ रहे है। इसको देखते हुए नए ट्रांसमिशन बिजली उपकेंद्र के साथ ही नए बिजली उपकेंद्र भी नए विकसित क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। वहीं पुराने लखनऊ व घनी आबादी वाले क्षेत्र में पावर ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे। इसके लिए जमीन भी तलाशी जाएगी, जिससे छोटे बिजली उपकेंद्र भी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बनाए जा सके। बिजली उपकेंद्र को डबल व त्रिपल सोर्स से लैस करने पर फोकस होगा। वीआइपी क्षेत्रों में एलटी केबल भी ओवरहेड न जाए, उन्हें ट्रंच लाइन में ले जाया जाए, इस पर भी विचार होगा।

सम्पादकीय

अब महिला पत्रकार पर गुस्सा हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहा बेईमान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्षों से तो बदतमीजी से पेश आते ही हैं पर अपने देश के पत्रकारों खासकर महिला पत्रकारों से वैसे पेश आते हैं ताजा घटना से पता चलता है। ट्रंप ने एनबीसी जैसी बड़ी टीवी नेटवर्क से एक इंटरव्यू के दौरान अचानक बातचीत बीच में ही खत्म कर दी। कार्यक्रम की होस्ट क्रिस्टन वेल्कर बार-बार उनके (ट्रंप के) कई दावों पर सवाल उठा रही थीं। रविवार को प्रसारित हुए कार्यक्रम 'मीट द प्रेस' में ट्रंप ने दावा किया कि कैलिफोर्निया में चल रहे प्राइमरी चुनाव और साल 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव दोनों ही धांधली पूर्ण थे। जब वेल्कर ने चुनावों में धांधली के दावे के समर्थन में सुबूत मांगे तो ट्रंप ने कहा, 'मुझे बस देखना और सुनना भर है।' इस पर वेल्कर ने कहा यह सुबूत नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने मीडिया पर बेईमान होने का आरोप लगाया और इंटरव्यू समाप्त करते हुए कहा, माफ कीजिए, अब इसे यहीं खत्म करते हैं। मेरे लिए बहुत हो गया यह इंटरव्यू अब खत्म है। इंटरव्यू शुरू होने के लगभग 50 मिनट बाद इसे छोड़ दिया। वेल्कर के सवालों के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कार्रवाई करनी जरूरी थी और यह अंतहीन युद्ध नहीं होगा। हम वहां कुछ महीनों के लिए रहेंगे और उसके बाद खतरा काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बातचीत उस दौर पर पहुंची और जब ट्रंप ने साल 2020 के चुनाव में धांधली का अपना पुराना, बिना सुबूत वाला दावा दोहराया तो क्रिस्टन वेल्कर ने उन्हें चुनौती दी। ट्रंप ने फिर कैलिफोर्निया के प्राथमिक चुनावों का जिक्र किया, जहां गवर्नर सहित कई पदों के लिए नवम्बर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में कौन से दो उम्मीदवार होंगे। यह तय करने के लिए वोटों की गिनती जारी थी। उन्होंने फिर आरोप लगाया, वे चुनाव में धांधली कर रहे हैं, पलटकर वेल्कर ने पूछा : क्या आपके पास इसके समर्थन में कोई सुबूत है? ट्रंप : मुझे सिर्फ देखना और सुनना है। वेल्कर ने बीच में टोका, लेकिन यह कोई सुबूत नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा वे बेईमान हैं बिल्कुल आपकी तरह। इस पर वेल्कर ने जवाब दिया निष्पक्षता की बात करें तो मैं बेईमान नहीं हूं। लेकिन बातचीत जारी रखें, इस पर ट्रंप ने उनसे कहा या तो आप बेईमान हैं या फिर बेवकूफ और यह कहते हुए ट्रंप उठ गए और कहा इसे यहीं खत्म करते हैं। मेरे लिए बहुत हो गया। शुक्रिया डार्लिंग, आपको अपने प्रेस को सुधारना चाहिए क्योंकि एक देश कभी महान नहीं बन सकता अगर उसकी प्रेस बेईमान है। हम इस महान पत्रकार को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी बेइज्जती सही पर डटी रहीं।

क्या इजरायल अमेरिका की जासूसी कर रहा है?

ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टकराव व बढ़ती रणनीतिक दूरियों ने पेंटागन की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय को इजरायली जासूसी का भय लगने लगा है। उसने चेतावनी दी है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी कड़ी इजरायली निगरानी का निशाना बन सकते हैं? एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के दो मौजूदा व एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआईए) ने हाल ही में इजरायल के लिए काउंटर इंटेलिजेंस खतरे के स्तर को क्रिटिकल यानी गंभीर कर दिया है। यह उनका सबसे ऊंचा आंतरिक मूल्यवान स्तर है। एक मौजूदा अधिकारी ने अमेरिकी पत्रकार को बताया कि अमेरिका पहले से ही इजरायल की आधिकारिक यात्राओं के दौरान सुरक्षा उपाय बरतता है क्योंकि इजरायली जासूसी एजेंसियों को जानकारी जुटाने के मामले में बहुत आक्रामक माना जाता रहा है। पेंटागन की नई चिंताओं से पता चलता है कि इजरायल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के संबंध में अमेरिकी रणनीतिक चर्चाओं व फैसलों की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली जासूसी नेटवर्क खासकर उनकी खुफिया एजेंसी ऐसे कामों के लिए दुनिया में बदनाम है। चौंकाने वाली बात यह है कि मोसाद ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी अमेरिका को भी नहीं बक्शा है?

योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे की अहम बॉडी छीनकर मुख्यमंत्री आफिस के कंट्रोल में क्यों की

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रमुख एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण को उस विभाग में स्थानांतरित कर दिया है, जो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन काम करता है. इसे राज्य की कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के अधीन कर दिया गया है. औद्योगिक विकास विभाग का नेतृत्व मंत्री नंद गोपाल नंदी कर रहे थे. इस बदलाव के बाद सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं और उनसे जुड़ी बुनियादी ढांचा योजनाएं सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में आ जाएंगी.

राज्य बीजेपी के पदाधिकारियों का मानना है कि यह फैसला नंदी के लिए एक झटका है. नंदी को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के करीब माना जाता है. नंदी ने इस फैसले पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात की.

उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास विभाग सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत चलने वाली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नीति बनाने और उनके समन्वय का काम करता है.

वढएकऊ्ञ को इस विभाग के अधीन लाकर सरकार का उद्देश्य फैसले लेने की प्रक्रिया और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और तेज तथा सुचारु बनाना है.

दिप्रिंट ने नंदी से प्रतिक्रिया लेने के लिए फोन कॉल और संदेश के जरिए संपर्क किया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. यदि उनकी प्रतिक्रिया मिलती है तो रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.

ऑर्डर में क्या लिखा है

सरकारी ऑर्डर के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद काम के बंटवारे में दिक्कतों को खत्म करना और फाइलों का जल्दी निपटारा पक्का करना है.

अभी तक, वढएकऊ्ञ प्रोजेक्ट से जुड़े बजट और अप्रूवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए प्रोसेस होते थे और मुख्यमंत्री तक पहुंचने से पहले कई लेवल पर क्लियरेंस की जरूरत होती थी. नए इंतजाम के तहत, उन्हें सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस के जरिए भेजा जाएगा, अधिकारियों का मानना है कि इससे अप्रूवल में तेजी आएगी और लागू करने में देरी कम होगी.

सीएमओ के अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट एजेंडा के सबसे साफ निशानों में से हैं और इसलिए, इन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है.

इन प्रोजेक्ट से जुड़े सीनियर अधिकारियों की पहले से ही मुख्यमंत्री तक सीधी पहुंच थी और वढएकऊ्ञ को इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के तहत लाने का मकसद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहलों को तेजी से पूरा करना पक्का करना है.

इस कदम से सीएमओ द्वारा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की सीधी निगरानी को मजबूत करने की उम्मीद है और

यह सरकार की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के एक अहम हिस्से के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर को दिखाता है.

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने दावा किया कि कुछ ह्लसीनियर अधिकारी मंत्री के साथ सहज नहीं थे, जिन्हें हर फाइल पर सवाल उठाने की आदत थी. इसलिए उट ने विकास के काम में तेजी लाने के पक्ष में फैसला किया. इसमें कुछ भी गलत नहीं है.ह्व

मंत्री और अधिकारियों के बीच तनाव

इस फैसले से मंत्री और अधिकारियों के कुछ हिस्सों के बीच अंदरूनी तनाव के बारे में भी अटकलें लगने लगी हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सूत्रों ने कहा कि हाल के ट्रांसफर पर नंदी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार के बीच असहमति की वजह से यह मामला हो सकता है.

खबर है कि यह विवाद मुख्यमंत्री के लेवल तक पहुंच गया था. वढएकऊ्ञ में अधिकारियों के अपॉइंटमेंट और डेपुटेशन को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिससे कई जानकारों ने इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव को उसी संदर्भ में देखा.

नंदी और उनके डिपार्टमेंट के सिविल सर्वेंट्स के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है.

पिछले साल, मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि सीनियर अधिकारी मंत्री के निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने पसंदीदा लोगों को गलत फायदे पहुंचा रहे हैं. नंदी ने सीनियर अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि वे अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, तय पॉलिसी और प्रोसेस को नजरअंदाज कर रहे हैं, और यहां तक कि ऑफिशियल फाइलें और रिकॉर्ड भी गायब होने दे रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, नंदी और वढएकऊ्ञ लीडरशिप के बीच तनाव मनोज कुमार सिंह के समय से है, जो अभी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के हेड हैं. मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले सिंह पहले वढएकऊ्ञ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) रह चुके हैं.

सूत्रों ने बताया कि सिंह के रिटायरमेंट और दीपक कुमार के अथॉरिटी के नए सीईओ बनने के बाद भी मतभेद बने रहे.

इस मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, नंदी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की देखरेख कर रहे सीनियर सिविल सर्वेंट्स के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हुए, और शायद यही उन वजहों में से एक था जिसने वढएकऊ्ञ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बदलने के फैसले पर असर डाला.

पहले, ऐसे झगड़ों का शायद ही कोई बड़ा नतीजा निकला हो.

राज्य सरकार को अक्सर विपक्षी पार्टियों और यहां तक कि अपने ही रैंक के लोगों से भी आलोचना का सामना करना पड़ा है कि कथित तौर पर सिविल सर्वेंट्स के हाथों में बहुत ज्यादा पावर जमा कर दी गई है.

मंत्रियों और विधायकों ने अक्सर शिकायत की है कि अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करते हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार के दोनों कार्यकालों के दौरान ऐसे कई टकराव सामने आए हैं.

2022 में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सबके सामने नाखुशी जताई और उनके काम करने के तरीके की शिकायत करते हुए फॉर्मल लेटर लिखे. एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने एक ऑफिशियल परफॉर्मेंस असेसमेंट के दौरान एक ऑफिसर को खराब रेटिंग देकर अपनी नाराजगी जाहिर की.

उसी साल एक और बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए चिट्ठी लिखी. खटीक ने आरोप लगाया कि अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि वह दलित समुदाय से थे और उन्होंने दावा किया कि उन्हें जरूरी डिपार्टमेंटल मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता था.

इस घटना से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी राज्य मंत्रियों को खास डिपार्टमेंटल ज़िम्मेदारियां दी जाएं. बीजेपी लीडरशिप के दखल के बाद ही मामला शांत हुआ.

तब से, कम से कम नौ मंत्रियों के लेटर कथित तौर पर लीक हो चुके हैं, जिनमें से कई ने ऑफिसरों की कथित बेपरवाही या उनके काम करने के तरीके की आलोचना करने पर चिंता जताई है.

राज्य सरकार ने सिविल सर्वेंट्स को कम से कम 15 रिमाइंडर जारी किए, जिसमें उन्हें सही व्यवहार बनाए रखने और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का पूरा सम्मान करने का निर्देश दिया गया.

कई मंत्रियों ने प्राइवेट तौर पर भी शिकायत की है कि उनके डिपार्टमेंट के काम में चीफ मिनिस्टर ऑफिस बहुत ज्यादा दखल देता है, यह चिंता सरकार के दोनों टर्म में बनी रही है.

'प्रोजेक्ट गंगा'.. समझिए कैसे रोजगार के साथ बदलेगी यूपी के 57 हजार ग्राम पंचायतों की तस्वीर

(जीएनएस)।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रोजेक्ट गंगा' की शुरूआत कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश का नया 'डिजिटल एक्सप्रेसवे' बताया. सीएम योगी ने मंगलवार को इस परियोजना का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट गंगा डिजिटल समावेशन को नई गति देगा और गांवों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेगा. इस योजना के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा.

प्रोजेक्ट गंगा के जरिए प्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इसके साथ ही 8 से 10 हजार डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर को तैयार किया जाएगा, जिससे एक लाख से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा. परियोजना के पहले चरण में 21 जिलों में काम शुरू हो रहा है. आगे इसे पूरे प्रदेश की लगभग 57 हजार ग्राम पंचायतों और करीब 8 हजार न्याय पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा. इससे गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने में मदद मिलेगी.

सीएम योगी का बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आज की जरूरत बन चुकी है. जितनी तेज इंटरनेट सुविधा होगी, विकास की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. सीएम ने मां गंगा की उपमा देते हुए कहा कि जिस तरह गंगा विकास और समृद्धि का आधार रही है, उसी तरह प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश की डिजिटल समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा. इससे डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने हिंदुजा ग्रुप को इस पहल के लिए बधाई दी. उन्होंने बताया कि 'सीएम युवा' योजना के तहत चयनित युवाओं को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में अपना उद्यम शुरू कर सकें. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने भी इस परियोजना को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ी पहल बताया. यह योजना उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

महुआ मोइत्रा को 'इश्क करो पार्टी' में क्यों देखना चाहते हैं 80 साल के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज? असली गेम प्लान क्या?

(जीएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने 80 साल की उम्र में अचानक एक नई 'पार्टी' लॉन्च कर दी। नाम है 'इश्क करो पार्टी'। नारा है, 'युद्ध नहीं, प्रेम करो'। सुनने में यह कोई रोमांटिक या मजाकिया आइडिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे उनका क्या असली इरादा है? और वे तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा को इसमें क्यों देखना चाहते हैं?

क्या यह सचमुच कोई नई राजनीतिक शुरूआत है या सिर्फ एक तेज धार वाला राजनीतिक व्यंग्य? इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि 'इश्क करो पार्टी' वास्तव में है क्या, इसका संदेश क्या है, महुआ मोइत्रा का जिक्र क्यों हो रहा है, और काटजू का असली गेम प्लान किस दिशा में जाता दिखता है।

इश्क करो पार्टीः नाम रोमांटिक, एजेंडा राजनीतिक

मार्कंडेय काटजू ने 'इश्क करो पार्टी' को एक मंच के रूप में पेश किया है, जो उनके मुताबिक, भारत में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और आम लोगों की बुनियादी समस्याओं पर जनसंघर्ष खड़ा करने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने अपने दोस्त इरफान अली (जो अमेरिका के न्यू जर्सी, प्रिंसटन में रहते हैं) के साथ मिलकर यह प्लेटफॉर्म खड़ा किया। इरफान ने तुरंत इसके लिए वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट और एक आधिकारिक ईमेल आईडी -- बना दी। खुद काटजू इस मंच के 'संरक्षक' की भूमिका में हैं, जबकि इरफान अली को 'अध्यक्ष'बताया गया है। काटजू साफ कह चुके हैं कि यह कोई पारंपरिक चुनावी राजनीतिक पार्टी नहीं है। वे इसे ऐसे मंच के रूप में देखते हैं जोः देशभक्त और जागरूक नागरिकों को जोड़े - धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाले नेतृत्व को सामने लाए - जाति-धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर जनदबाव बनाए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को इस 'पार्टी' का मुख्य मैदान बनाया गया है। यही वजह है कि इसका पहला औपचारिक एलान भी (पूर्व ट्विटर) और ईमेल के जरिए किया गया।

जस्टिस काटजू ने यह मंच अभी क्यों शुरू किया?

काटजू के मुताबिक, भारत इस समय बेहद गंभीर संकटों से जूझ रहा है। वे जिन मुद्दों को सबसे बड़े संकट के रूप में देखते हैं, वे हैं... व्यापक गरीबी और बेरोजगारी बच्चों में कुपोषण का खतरनाक स्तर (ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे इंडिकेटर्स का हवाला देकर वे कहते हैं कि हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप में प्रभावित है)। आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की भारी कमी। महंगाई, खासकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें। जाति और धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा।

काटजू का तर्क है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय समाज को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन, उनके अनुसार, मौजूदा राजनीतिक ढांचा और बड़े-बड़े नेता लोगों को जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के आधार पर बांटने में लगे हैं। यहीं से 'इश्क करो पार्टी' का आइडिया आता है। उनकी नजर में यह एक ऐसा मंच है जो विभाजन और नफरत की राजनीति के खिलाफ 'दिल' और 'दिमाग' दोनों स्तर पर प्रतिरोध खड़ा करे और लोगों को बतौर नागरिक जोड़ने की कोशिश करे।

यह 'इश्क' कौन-सा है? सूफी अर्थ बनाम रोमांटिक गलतफहमी

'इश्क-ए-हकीकी' का मतलब है ईश्वर से, या किसी उच्च आदर्श से वह प्रेम, जिसके लिए इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर सके। यह ऐसा भाव है जो सीमाओं से परे है, न जाति, न धर्म, न भाषा, न नस्ल - कुछ भी आड़े नहीं आता।

काटजू अक्सर मिर्जा गालिब के शेर का उदाहरण देते हैं:

'इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश 'गालिब' कि लगाए न लगे और बुझाए न बने!'

उनका कहना है कि 'इश्क करो पार्टी' में 'इश्क' का मतलब है - देश के हर नागरिक के लिए प्रेम, मानवीय करुणा और बराबरी की भावना। यानि एक तरह का राजनीतिक और सामाजिक 'सूफी इश्क', जो विभाजन की जगह एकता पर जोर देता है।

'इश्क करो पार्टी' की एंट्री ऐसे समय में हुई, जब एक और डिजिटल-युग की 'व्यंग्यात्मक' पार्टी पहले से सुर्खियों में थी 'कॉकरोच जनता पार्टी'। कॉकरोच जनता पार्टी (उखढ) के संस्थापक अभीजित दीपके हाल के दिनों में दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। यह 'पार्टी' खुद को एक तंजिया, लेकिन राजनीतिक तौर पर एंगेज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर रही है और उसने काफी हद तक ञ्रल्ल` और युवा सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। उनका प्लान है कि अपनी मांगों और विरोध-प्रदर्शनों को राज्यस्तर पर पूरे देश में फैलाया जाए।

इसी बीच, काटजू ने 'इश्क करो पार्टी' की घोषणा की। वे खुलकर कह रहे हैं कि युवा, खासकर ञ्रल्ल`, आज एक ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीति पर हावी हैं । हेट स्पीच और ध्रुवीकरण सामान्य बात बन चुके हैं। जोश बहुत है, पर दिशा कई बार भटक जाती है। काटजू खुद को युवाओं के लिए एक वैकल्पिक 'पथप्रदर्शक' के रूप में पेश करते हैं और कहते हैं कि 'युद्ध नहीं, प्रेम करो' सिर्फ स्लोगन नहीं, बल्कि राजनीति में 'ूमैनिटी और नैतिकता वापस लाने का संदेश है।

असली गेम प्लानः पार्टी या पॉलिटिकल व्यंग्य?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या काटजू सचमुच कोई गंभीर राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, या यह उनके पहले के प्रयोगों की तरह एक तीखा व्यंग्य है?

वे पहले 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसी कल्पित पार्टी का जिक्र कई बार कर चुके हैं, जहां वे भ्रष्ट, अवसरवादी राजनीति पर तंज कसते थे। 'इश्क करो पार्टी' भी बहुत हद तक उसी सिलसिले की अगली कड़ी लगती है, लेकिन इस बार फोकस केवल तंज पर नहीं, बल्कि एक 'पॉजिटिव' वैल्यू यानी प्रेम और एकता पर रखा गया है। डिजिटल युग में जहां हर चीज कंटेंट, मीम और ट्रेंड में बदल जाती है, काटजू का असली दांव यही लगता है कि वे गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए व्यंग्य और प्रतीकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। 'पार्टी' का फॉर्मेट चुनकर वे दिखाना चाहते हैं कि अगर नफरत की राजनीति पार्टी बन सकती है, तो 'इश्क' भी एक राजनीतिक विचार बन सकता है।

इस पूरी कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा वह स्क्रीनशॉट है, जो सोशल मीडिया पर घूमता रहा। उसमें दावा किया गया कि काटजू ने महुआ मोइत्रा को 'इश्क करो पार्टी' में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। यह बात तुरंत सुर्खियों में इसलिए आ गई क्योंकि महुआ मोइत्रा अपनी आक्रामक, बेलौस और तीखी राजनीतिक शैली के लिए जानी जाती हैं। संसद और टीवी डिबेट्स में उनके भाषण अक्सर सरकार पर सीधे, कटु और धारदार हमले माने जाते हैं।

'इश्क करो पार्टी' को समझने के लिए काटजू की पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड पर एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि वही इस पूरे प्रयोग का टोन सेट करती है। 20 सितंबर 1946 को जन्मे मार्कंडेय काटजू कानून की गहरी परंपरा वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता एस.एन. काटजू इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उनके दादा डॉ. कैलाश नाथ काटजू आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहे, आजाद भारत में केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्री रहे, और एक बड़े राजनेता व वकील माने जाते थे।

डिजिटल प्रोवोकेशनः उम्र 80, अंदाज पूरी तरह ऑनलाइन

काटजू की मौजूदा रणनीति को अगर एक वाक्य में समझना हो तो वह है - 'डिजिटल प्रोवोकेशन'। वे (पूर्व ट्विटर), फेसबुक और ब्लॉग्स के जरिए ऐसी बातें लिखते हैं, जो तुरंत बहस, ट्रोलिंग और वायरल कंटेंट बन जाएं। वे पारंपरिक राजनीतिक दल बनाने या चुनाव मैदान में उतरने की दिशा में नहीं दिखते, लेकिन राजनीतिक विमर्श को झकझोरते रहने की चिंता लगातार दिखती है। 'इश्क करो पार्टी' उनके इसी डिजिटल एजेंडा का नया एपिसोड है, जिसमें वे नफरत भरे नेरेटिव के बीच अचानक 'प्रेम करो' जैसी बात उछालकर सबको असहज कर देते हैं।

अपना संविधान, अपनी पुलिस, अपनी सरकार, फिर भी इस्लामाबाद के इशारों पर क्यों चलता है पीओके?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। खअअउ ने 9 जून को मुजफ्फराबाद और रावलकोट में प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इन घटनाओं ने एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ढङ्गङ का अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, संविधान और यहां तक कि अलग झंडा भी है। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सत्ता संरचना के हाथों में माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह व्यवस्था बनी कैसे और पाकिस्तान इसे क्यों बनाए रखना चाहता है?

ढङ्गङ की शुरूआत कैसे हुई?

आज जिस क्षेत्र को भारत, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) कहता है, उसका इतिहास 1947 के भारत-विभाजन से जुड़ा हुआ है। यह लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। पाकिस्तान इसे "आजाद जम्मू-कश्मीर" कहता है, जबकि भारत इसे अपने जम्मू-कश्मीर का अवैध रूप से कब्जाया गया हिस्सा मानता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान

समर्थित पश्तून कबायली लड़ाकों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया था। उस समय जम्मू-कश्मीर एक रियासत थी, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। विभाजन के बाद उन्होंने तत्काल भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला नहीं किया था।

लेकिन जैसे-जैसे कबायली हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और पाकिस्तान तथा भारत के बीच पहला युद्ध शुरू हो गया। करीब 14 महीने तक चले इस युद्ध के बाद 31 दिसंबर 1948 की रात युद्धविराम लागू किया गया। 1 जनवरी 1949 से युद्धविराम रेखा प्रभावी हुई, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर का लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया।

आज पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा तथाकथित "आजाद जम्मू-कश्मीर" (AJK) है और दूसरा गिलगित-बाल्टिस्तान (GB)। गिलगित-बाल्टिस्तान अकेले PoK के कुल क्षेत्रफल का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा बनाता है। भारत का आधिकारिक रुख यह है कि PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों ही 1947 में हुए विलय के आधार पर भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।

PoK का प्रशासन 1974 के "आजाद जम्मू-कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम" के तहत संचालित होता है। इसी व्यवस्था के आधार पर वहां अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, न्यायिक प्रणाली और पुलिस बल मौजूद हैं। 1974 के इस अंतरिम संविधान और पाकिस्तान के संविधान के कुछ प्रावधान मिलकर यह तय करते हैं कि PoK और इस्लामाबाद के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा। कागजों पर देखने पर ऐसा लगता है कि PoK को काफी हद तक स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वास्तविक फैसले लेने की शक्ति अभी भी पाकिस्तान के केंद्रीय नेतृत्व के पास ही रहती है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊ : युवक को बंधक बनाकर लोहे की रॉड से पीटा, हालत गंभीर; आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस

(जीएनएस)।

लखनऊ। बीबीडी इलाका स्थित बीसीसी शक्ति अपार्टमेंट में युवक को वहीं रहने वाले युवकों ने बंधक बनाकर पीटा। पीड़ित के पिता ने अपार्टमेंट में रहने वाले एक युवक और उसके साथियों पर बंधक बनाकर पीटने, मोबाइल तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने की तहरीर स्थानीय थाने में दी। इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

तिवारीगंज स्थित बीसीसी शक्ति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर-814 निवासी पंकज यादव के मुताबिक, सात जून की रात उनका बेटा मयंक दैनिक उपयोग का सामान लेकर लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। इसी दौरान फ्लैट नंबर-401 में रहने वाले विपिन कुमार सिंह अपने साथियों अनुराग मिश्रा, अभि ठाकुर और राज मिश्रा के साथ वहां पहुंचे और उनके बेटे को धक्का दे दिया।

बेटे को लिफ्ट से बाहर खींचा

आरोपितों ने उनके बेटे को लिफ्ट से बाहर खींच लिया। गालियां दी, करीब 20 मिनट तक बंधक बनाकर पीटा। लोहे के पाइप से हमला किया गया। सिर व शरीर के कई हिस्सों में चोट आई हैं। मोबाइल भी तोड़ दिया।

बेहोश होने पर उस पर पत्थर से वार किया गया। पिता ने बताया कि आरोपित अपराधी हैं। पूरा परिवार दहशत में है। इंस्पेक्टर राम सिंह के मुताबिक सीसी फुटेज की मदद से मामले में साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं।

लखनऊ का कायाकल्प: एलडीए तोड़ेगा कैलाशकुंज और विकासदीप कॉम्प्लेक्स, 110 करोड़ से बनेंगे 13 मंजिला मॉल और प्रीमियम फ्लैट्स

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुसैनगंज का विकासदीप, इंदिरा नगर का कैलाशकुंज, अलीगंज और कपूरथला के पुराने व्यावसायिक परिसरों को तोड़कर उनकी री-स्ट्रक्चरिंग और री-मॉडलिंग की जाएगी. इस महायोजना की शुरूआत सबसे पहले इंदिरा नगर के कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स से होगी और धीरे-धीरे यह सिलसिला आगे बढ़ेगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण अब शहर के इन सभी बेहद पुराने और जर्जर हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से बहुमंजिला बनाने जा रहा है. इसकी शुरूआत अयोध्या रोड पर स्थित करीब 40 साल पुराने प्रसिद्ध कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स को ढहाने के साथ की जाएगी.

कैलाशकुंज की जगह बनेगी 13 मंजिला आधुनिक इमारतः यहां की वर्तमान जर्जर हो चुकी 13 मंजिला पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर उसकी जगह एक नई और बेहद आधुनिक गगनचुंबी बिल्डिंग बनाई जाएगी. एलडीए की नई योजना के मुताबिक इसमें नीचे के फ्लोर पर दुकानें और कॉर्पोरेट ऑफिस रहेंगे, जबकि ऊपर की मंजिलों पर प्रीमियम आवासीय फ्लैट्स बनाए जाएंगे. एलडीए का दृढ़ मानना है कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आगे चलकर लखनऊ में शहरी री-डेवलपमेंट (पुनर्विकास) का पहला बेहतरीन उदाहरण बनेगा. वर्तमान में कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स प्राइम लोकेशन पर कुल 6046 वर्गमीटर की विशाल सरकारी जमीन पर बना हुआ है.

जर्जर दुकानों और अवैध कब्जों पर LDA का एक्शनः इस पुराने परिसर में करीब 280 दुकानें मौजूद हैं, लेकिन 40 साल पुरानी होने के कारण इसकी मुख्य बिल्डिंग कई जगहों से तकनीकी रूप से बेहद कमजोर हो चुकी है. हाल ही में जब एलडीए की टीम ने इसका विस्तृत सर्वे कराया, तो पता चला कि बहुत सी दुकानें यहाँ सालों से बंद पड़ी हैं. इसके साथ ही परिसर के कॉमन एरिया और पार्किंग स्पेस में भी स्थानीय

लोगों ने अवैध रूप से पक्का कब्जा कर रखा है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह जगह अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बेहद शानदार और महंगी लोकेशन पर स्थित है.

PPP मॉडल रद्द, अब छऊ्अ खुद खर्च करेगा 110 करोड़ः परंतु समय पर रखरखाव न होने और बिल्डिंग के अत्यधिक पुरानी पड़ जाने से इस बेशकीमती जमीन का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. इसलिए जनसुरक्षा और सुंदरीकरण के मद्देनजर इसे पूरी तरह तोड़कर नई बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने का कड़ा फैसला लिया गया है. एलडीए अब खुद अपने स्तर पर इस बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण कराएगा और इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है. पहले इसे PPP मोड यानी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बनाने का प्लान था, लेकिन अब प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्चे पर काम करेगा.

पुराने दुकानदारों को मिलेगा सवा गुना बड़ा स्पेसः प्रस्ताव के अनुसार, नई बनने वाली आधुनिक बिल्डिंग करीब 45 मीटर ऊंची होगी और इसमें कुल 13 मंजिलें तैयार की जाएंगी. इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में एलडीए द्वारा करीब 110 करोड़ रुपये की भारी रकम खर्च की जाएगी. इसके नीचे की तीन मंजिलों यानी भूतल (ग्राउंड फ्लोर), पहले और दूसरे तल पर व्यावसायिक दुकानें और ऑफिस स्पेस दिया जाएगा. इसके ऊपर की बची हुई सभी मंजिलों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस 3 BHK वाले प्रीमियम फ्लैट बनाए जाएंगे.

कैलाशकुंज के बाद अलीगंज और गोमती नगर की बारीः इस री-डेवलपमेंट योजना से कैलाशकुंज के पुराने और पंजीकृत दुकानदारों को सीधा और बड़ा आर्थिक फायदा मिलने वाला है. एलडीए के अधिकारी वर्तमान में उन सभी दुकानदारों से सीधे बात करके इस संबंध में विधिक सहमति ले रहे हैं. आपसी बातचीत में तय हुआ है कि पुरानी बिल्डिंग में जिनकी जितनी बड़ी दुकान है, उन्हें नई बिल्डिंग में उससे सवा गुना बड़ा एरिया दिया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी आवंटी की पुरानी दुकान 100 वर्गफुट की है, तो नई आलीशान बिल्डिंग में उसे 125 वर्गफुट की बड़ी दुकान मिलेगी.

उजाला कॉम्प्लेक्स का भी बदलेगा नक्शा, तैयारी तेजः इससे पुराने वैध आवंटियों को भी पहले से बड़ा और बेहतर माहौल में अपना कारोबार करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देने के कड़े निर्देश दिए हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि कैलाशकुंज को पूरे लखनऊ के लिए री-डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल बनाया जाएगा. उन्होंने आगामी योजनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि इसके तुरंत बाद अलीगंज और गोमती नगर की व्यावसायिक संपत्तियों की बारी है.

अलीगंज में बनेगी 14 मंजिला भव्य विंगः एलडीए अपनी इस महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना के तहत सिर्फ कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. अलीगंज के सेक्टर-जी में स्थित पुराने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए भी इसी तर्ज पर री-डेवलपमेंट का नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. अलीगंज का यह पुराना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करीब 11,000 वर्गमीटर में फैला है और इसमें वर्तमान में करीब 100 दुकानें संचालित हैं. यहाँ पर एलडीए द्वारा 14 मंजिला नई और भव्य कमर्शियल-कम-रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है.

250 नई दुकानें और 72 प्रीमियम फ्लैट्स का तोहफाः इस प्रस्तावित अलीगंज प्रोजेक्ट के तहत नई बिल्डिंग में 250 आधुनिक दुकानें और 72 आलीशान आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे. यहाँ बनने वाले सभी फ्लैट भी उच्च आय वर्ग के लिए 3 BHK कैटेगरी के ही निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा, पॉश इलाके गोमती नगर में स्थित पुराने 'उजाला कॉम्प्लेक्स' को भी दोबारा से आधुनिक स्वरूप में बनाने की योजना पर काम चल रहा है. इस व्यापक कदम से लखनऊ के पुराने बाजारों का कायाकल्प होगा और शहर को जाम व जर्जर भवनों से मुक्ति मिलेगी.

अर्पण केंद्र क्या है? दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन पर हो रही शुरू ये सुविधा, इस नयाब पहल के बारे में

(जीएनएस)।

अक्सर में बगैर इस्तेमाल के कपड़े अलमारी में जगह घेरते हैं। अगर आप भी ऐसे कपड़ों को फेंकने के बजाय उनका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली में बढ़ते टेक्सटाइल कचरे को कम करने और जरूरतमंदों तक उपयोगी संसाधन पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार और DMRC ने एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया है।
'

अर्पण केंद्र' नाम की इस योजना के तहत मेट्रो यात्रियों को पुराने और उपयोग योग्य कपड़े दान करने की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य कपड़ों की बबार्दी रोकना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और पुनर्चक्रण के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

क्या है 'अर्पण केंद्र'?

'अर्पण केंद्र' एक विशेष कपड़ा दान अभियान है, जिसके तहत दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर कलेक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे। यात्री अपने घरों में पड़े पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़ों को इन बॉक्स में जमा कर सकेंगे। इससे लोगों को कपड़े दान करने के लिए अलग से किसी संस्था या केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कपड़ों को मिलेगा नया जीवन

कलेक्शन बॉक्स में जमा किए गए कपड़ों को उनकी स्थिति और उपयोगिता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया

जाएगा। इसके बाद गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की मदद से इन कपड़ों को रिसाइकिल कर नए और उपयोगी उत्पादों में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

टेक्सटाइल कचरे की समस्या से निपटने की कोशिश

विशेषज्ञों के अनुसार, टेक्सटाइल वेस्ट आज पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर साल बड़ी मात्रा में फेंके जाने वाले कपड़े लैंडफिल साइट्स पर दब जाते हैं, जिससे प्रदूषण और कचरे की समस्या बढ़ती है। 'अर्पण केंद्र' पहल इस चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह अभियान स्वच्छ, हरित और टिकाऊ दिल्ली के लक्ष्य को भी मजबूती देगा।

इन 10 मेट्रो स्टेशनों पर लगाए जाएंगे कलेक्शन बॉक्स

योजना के पहले चरण में दिल्ली के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर कपड़ा संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें शाहदरा (रेड लाइन), मोहन एस्टेट (वायलेट लाइन), रोहिणी वेस्ट (रेड लाइन), लाजपत नगर (वायलेट और पिंक लाइन), मालवीय नगर (येलो लाइन), मयूर विहार फेज-क (ब्लू और पिंक लाइन), हौज खास (येलो और मैजेंटा लाइन), पंजाबी बाग वेस्ट (पिंक और ग्रीन लाइन), द्वारका (ब्लू लाइन) और शालीमार बाग (पिंक लाइन) मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।

सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ

इस पहल से न केवल कपड़ों की बबार्दी कम होगी, बल्कि जरूरतमंद समुदायों तक संसाधन पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, रिसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर भी विकसित हो सकेंगे। 'अर्पण केंद्र' को दिल्ली में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्ययनाथ और लेफ्ट... एक संगम जिसने केरल चुनाव के नतीजे बदल दिए

(जीएनएस)।

क्या केरल में सत्ता परिवर्तन में धर्म की राजनीति की भी बड़ी भूमिका थी? विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के बाद लेफ्ट फ्रंट एलडीएफ का नेतृत्व करने वाली सीपीएम ने ही यह बात स्वीकार की है. सीपीएम का यह भी मानना है कि ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़ा जाना भी नुकसानदेह साबित हुआ.

केरलम में विधानसभा चुनाव से पहले एक सम्मेलन हुआ था. ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन. 20 सितंबर को सम्मेलन का आयोजन सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर के पास पंपा में हुआ था. केरलम में सत्ता परिवर्तन के करीब महीना भर बाद ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन का खास तौर पर जिक्र हो रहा है, और केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन की हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है.

खास बात यह है कि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक संदेश भी पढ़ा गया था. ऐसा तब हुआ जब केरलम बीजेपी के नेता भी सरकारी आयोजन का विरोध कर रहे थे. बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस और बाकी यूडीएफ नेताओं की तरफ से तत्कालीन

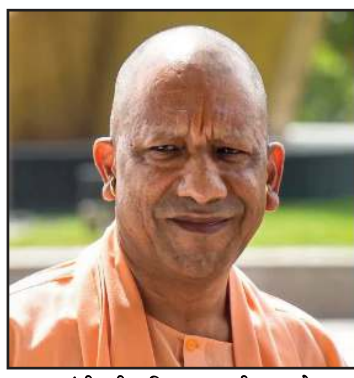

मुख्यमंत्री पी. विजयन की आलोचना हो रही थी. नेताओं का आरोप था कि सीपीएम धर्म और राजनीति को मिलाकर चुनाव जीतने के लिए हिंदू कार्ड का इस्तेमाल कर रही है.

केरलम विधानसभा चुनावों में एलडीएफ की हार की विस्तृत समीक्षा के बाद उढक(ट) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने माना है कि ऐसी चीजों से गलत संदेश गया, जो एलडीएफ की हार की वजह बना. प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमवी गोविंदन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़ा जाना भी सही नहीं था.

ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था. आयोजन के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री और एलडीएफ नेता का मकसद था, सबरीमाला को वैश्विक तीर्थस्थल बनाना, अय्यप्पा में आस्था रखने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को बुलाना - और 2018-19 के सबरीमाला विवाद के बाद खराब हुई छवि को सुधारने का प्रयास करना. असल में, सबरीमाला विवाद के दौरान मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मुद्दे पर पी. विजयन सरकार के स्टैंड से लोगों में भारी नाराजगी देखी गई थी.

और अब उढक(ट) स्वीकार कर रही है कि 2025 में हुए ग्लोबल अय्यप्पा डिवोटीज कॉन्फ्रेंस, जिसे हिंदू वोटर को साधने की एक और कोशिश के रूप में देखा गया, पूरी तरह उल्टा पड़ गया. उढक(ट) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने मीडिया से कहा, अय्यप्पा सम्मेलन का आयोजन देवस्वम बोर्ड ने किया था... लेकिन, इसे सरकारी आयोजन के रूप में प्रचारित किए जाने के कारण लोगों में भ्रम पैदा हुआ... आरएसएस के प्रमुख नेताओं में से एक, योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़ना सही नहीं था.

अव्वल तो केरलम बीजेपी भी तत्कालीन सरकार चला रहे पी. विजयन के सरकारी आयोजन का विरोध कर रही थी, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आयोजन को खुला समर्थन मिला. ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन बेशक त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का आयोजन।

समाज और संस्कृति को सही दिशा देता है अच्छा साहित्य

मुंबई, 11 जून। प्रतीक्षा मेमोरियल एज्युकेशनल ट्रस्ट, मुंबई के 20 वें वार्षिक सम्मेलन का गरिमापूर्ण समारोह बुधवार, 10 जून, 2026 को अनंत शुभकामनाएॅ दीं। परिचर्चा में भाग लेने वाले मनीषियों में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के निवर्तमान कार्याध्यक्ष डॉ. शीतला स्तुति पर प्रस्तुत आकर्षक कत्थक नृत्य के साथ हुआ। सभी का स्वागत करते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉ. कृपाशंकर मिश्र ने अपनी प्रस्तावना में पाण्डेय क्रान्ति, राजेन्द्र मिश्र, डॉ. मृदुल तिवारी महक, वाचस्पति तिवारी, श्रीधर आत्मिक मिश्र, प्रमोद पाण्डेय, विनोद पाण्डेय, रामजीत गुप्त,

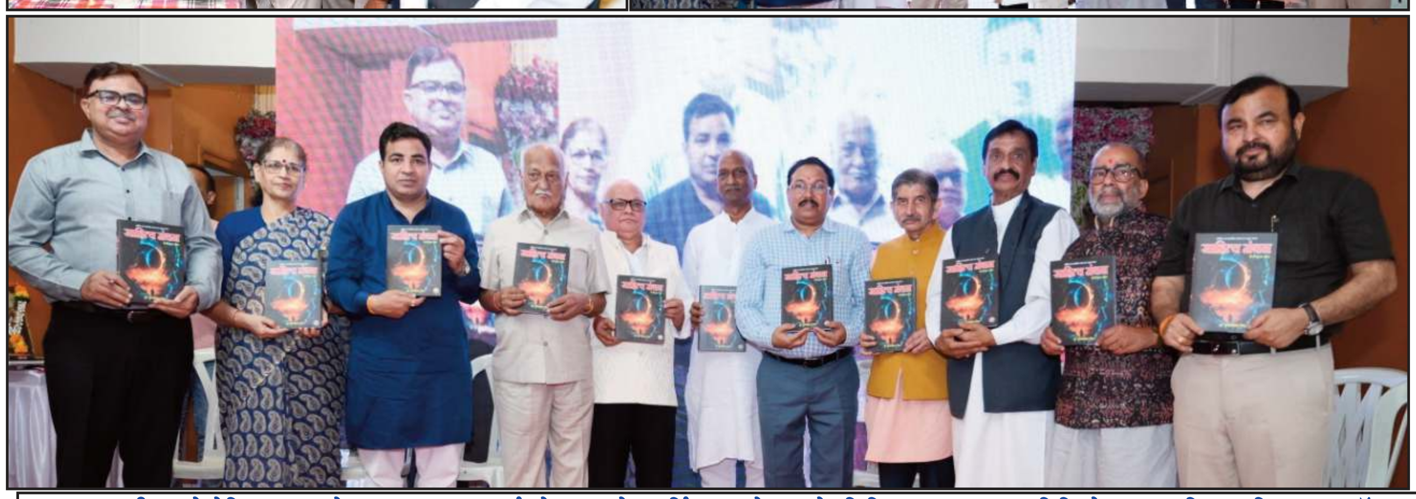

प्रतीक्षा मेमोरियल एज्युकेशनल ट्रस्ट, मुंबई के 20 वें वार्षिक सम्मेलन में विभिन्न गणमान्य अतिथियों द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृपाशंकर मिश्र द्वारा नवसृजित हिन्दी काव्य-संग्रह "साहित्य मंथन" के लोकार्पण तथा सबके द्वारा डॉ. मिश्र के सामूहिक अभिनंदन का दृश्य। तीसरे चित्र में लोकार्पण समारोह की शुरूआत में दीप प्रज्ज्वलन करते हुए समारोह के अध्यक्ष डॉ. सुधाकर मिश्र।

मुंबई के प्रमुख उपनगर गोरेगॉव के केशव गोरे सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मंच पर उपस्थित विभिन्न प्रबुद्ध और गणमान्य अतिथियों ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृपाशंकर मिश्र द्वारा नवसृजित हिन्दी काव्य-संग्रह "साहित्य मंथन" का लोकार्पण किया। डॉ. मिश्र की नवीनतम पुस्तक पर परिचर्चा के दौरान विभिन्न अतिथि वक्ताओं ने कहा कि अच्छा साहित्य हमेशा समाज एवं संस्कृति को सही दिशा देता है और इस कसौटी पर डॉ. मिश्र की सभी पुस्तकें पूरी तरह खरी उतरती हैं।

इस सुरुचिपूर्ण समारोह की अध्यक्षता हिन्दी साहित्य के वरिष्ठतम हस्ताक्षर डॉ. सुधाकर मिश्र ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में डॉ. कृपाशंकर मिश्र की सृजनधर्मिता एवं लेखकीय गुणवत्ता की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन किया और उनकी भावी सृजन यात्रा के लिए प्रसाद दुबे, मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. करुणा शंकर उपाध्याय, वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रमुख राजनेता प्रो. डॉ. दयानंद तिवारी, वरिष्ठ विदुषी डॉ. उषा मिश्रा, वरिष्ठ शायर डॉ. सागर त्रिपाठी, वाराणसी से आये विद्वान डॉ. कपिलदेव प्रसाद मिश्र, नागपुर से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार श्रीराम कृष्ण सहस्रबुद्धे, राजकुमार मिश्र और समारोह का कुशल संचालन कर रहे डॉ. उमेशचंद्र शुक्ल ने "साहित्य मंथन" पुस्तक और डॉ. कृपाशंकर मिश्र की सृजन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विस्तृत एवं समीक्षात्मक विचार प्रकट किये। समारोह का शुभारम्भ जाने-माने संस्कृत विद्वान श्रीराम व्यास उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना, डॉ. सुधाकर मिश्र एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन तथा सुश्री कनिष्का अंकित मिश्रा द्वारा गणेश समारोह के सम्पूर्ण नियोजन एवं संस्था की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ गीतकार एवं मीडिया सलाहकार गजानन महतपुरकर, मशहूर फिल्मी गीतकार डॉ. देवमणि पांडेय, वरिष्ठ साहित्यकार बोधिसत्व, डॉ. नीलिमा पाण्डेय, श्रीमती आभा बोधिसत्व, श्रीमती सत्यभामा सिंह, राजकुमार मिश्र, डॉ. दिनेश वर्मा, डॉ. रोशनी किरण, डॉ. किरण मिश्रा, श्रीमती पल्लवी रानी, श्रीमती किरण तिवारी और ओमप्रकाश तिवारी सहित विभिन्न वरिष्ठ कलमकारों को संस्था की ओर से प्रशस्ति-पत्र, पुष्प गुच्छ तथा नवलोकार्पित पुस्तक की प्रति देकर एवं शॉल ओढ़ाकर "साहित्य गौरव सम्मान" से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले अन्य कलमकारों में शिवप्रकाश जौनपुरी, मनोज नायक, लाल बहादुर कमल, नन्दन मिश्र त्यागी, सुरेश मिश्र, मिथिलेश मिश्र, प्रमोद उपाध्याय, नीतू नन्दलाल क्षितिज, ए. पी. द्विवेदी, श्रीमती रोमा झा, श्रीमती कुसुम तिवारी, इन्दिरा तिवारी, श्रीमती अमिता गुजराल, श्रीमती जागृति सिन्हा, राजनाथ शर्मा, हरिशंकर मिश्र, संतोष मिश्र, सुरेश दुबे, कृष्ण कान्त मिश्र, राम सिंह, अमरनाथ तिवारी, गौरी शंकर तिवारी, हरिश्चंद्र पाण्डेय, आनन्द पाण्डेय केवल, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, विनय शर्मा दीप, अरुण दुबे, डॉ. प्रमोद पाण्डेय, सूर्यकुमार तिवारी एवं समस्त मानस ट्रस्ट परिवार, संजय द्विवेदी, अनिल कुमार राही, राकेशमणि तिवारी, आर के सर चुलबुल, अवधेश विश्वकर्मा और एस वी राघवन शामिल हैं। समारोह के संयोजन में वसीम और उनके सक्रिय सहयोगियों ने समर्पित भाव से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में संस्था के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृपाशंकर मिश्र ने सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया।

केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर यूपी में मनेगा विकास का महापर्व, लखनऊ से वाराणसी तक सीएम योगी रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में भव्य आयोजन होने जा रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोकभवन में राजग (NDA) के सहयोगी दलों के साथ मीडिया संवाद करेंगे और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही सीएम योगी नोएडा के लिए 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और शाम को वाराणसी में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे.

(जीएनएस)।

लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में एक भव्य उत्सव का आगाज होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार इस अवसर को 'विश्वास, विकास और जनकल्याण के गौरवपूर्ण 12 वर्ष' के रूप में पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाएगी. इस महा-आयोजन के तहत मुख्यमंत्री सुबह राजधानी लखनऊ और शाम को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां वे मोदी सरकार के सुशासन, जनकल्याण और विकास यात्रा की बड़ी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे.

मोदी सरकार के सुशासन के 12 वर्ष की उपलब्धियों को बताएगी योगी सरकार

सुशासन को समर्पित पीएम मोदी के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में मीडिया संवाद करेंगे. मोदी सरकार के नेतृत्व में जनकल्याण, अवस्थापना एवं आस्था को मिले सम्मान के विषय में संपूर्ण जानकारी भी देंगे. मोदी सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा को लेकर यहां प्रदर्शनी भी लगेगी. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

सरकार के साथ ही भाजपा संगठन व सहयोगी दल के नेता भी रहेंगे मौजूद

भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन की तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष/केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी रहेंगे. साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री व सहयोगी दल अपना दल (एस) के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद, सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर व राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार भी रहेंगे.

लखनऊ में आरक्षी भर्ती परीक्षा में दोस्त की जगह साल्वर गिरफ्तार, फजीवाड़े का खुलासा

आरक्षी भर्ती परीक्षा में दोस्त की जगह परीक्षा देने पहुंचे मथुरा निवासी साल्वर राम औतार को कैसरबाग से गिरफ्तार किया गया। बाबा ठाकुरदास इंटर कालेज में फजीवाड़ा पकड़ा गया।

(जीएनएस)।

लखनऊ। आरक्षी भर्ती परीक्षा में साल्वरों के पकड़े जाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा घटना कैसरबाग के बाबा ठाकुरदास इंटर कालेज से सामने आई जहां दोस्त के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे मथुरा निवासी युवक को पुलिस ने पकड़ा। परीक्षा केंद्र प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक, मथुरा के नगला सीसराम निवासी राम औतार अपने दोस्त बीरु की जगह पर बाबा ठाकुरदास इंटर कालेज में परीक्षा देने पहुंचा था। स्कैनिंग के दौरान उसकी हरकतें संदिग्ध लगी। सख्ती से उसकी जांच की गई तो फजीवाड़ा सामने आया। परीक्षा केंद्र प्रभारी अरुण कुमार ने इसकी सूचना कैसरबाग पुलिस को दी।

यह भी पढ़ें– यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में 60 हजार पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती, आयोग ने शुरू की तैयारी

मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने आरोपित से पूछताछ की तो उसने दोस्त की जगह परीक्षा में शामिल होने की बात कही। जांच में उसके पास से परीक्षा से संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर उसके बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है।

एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव लखनऊ में गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई

(जीएनएस)।

एनआरएचएम घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। विभिन्न जिलों में हुई कथित अनियमितताओं की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बहराइच की पयागपुर सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव को विजिलेंस ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ एनआरएचएम घोटाले में भी कई एफआईआर दर्ज हैं। मुकेश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी और भाई को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसकी जांच जारी है। विजिलेंस ने बीते 10 दिन के दौरान श्रावस्ती और बलरामपुर में एनआरएचएम योजना के तहत कराए गए कामों में घोटाला करने के आरोप में भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया हैं।

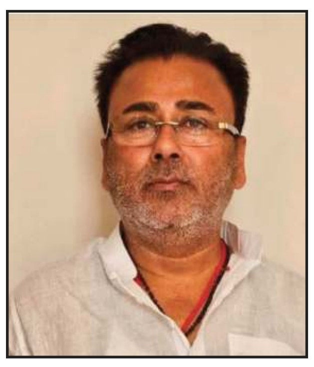

आईजी विजिलेंस मंजिल सैनी ने बताया कि मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप श्रीवास्तव के खिलाफ वर्ष 2023 में विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की एफआईआर दर्ज की थी। शासन ने उनके खिलाफ वर्ष 2021 में विजिलेंस को गोपनीय जांच करने का आदेश दिया था। विजिलेंस ने जांच कर अपनी अंतिम रिपोर्ट 12 अक्टूबर 2022 को शासन को सौंपी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश श्रीवास्तव ने अपनी आय के सभी वैध स्रोतों से कुल 1,12,65,635 रुपये अर्जित किए थे, जबकि चल-अचल संपत्तियों को खरीदने और भरण-पोषण में 1,79,96,526 रुपये व्यय किए। इस तरह उन्होंने अपनी वैध आय से 67,30,891 रुपये (59.74 प्रतिशत) अधिक व्यय किए। इस अंतर के बारे में वह विजिलेंस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे।

जिसके बाद शासन की अनुमति पर विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की थी। विजिलेंस ने उनके ठिकानों पर मारे गए छापों में भ्रष्टाचार के पुख्ता सुबूत जुटाए थे। इसकी गहन विवेचना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे ईडी भी बीते वर्ष गहन पूछताछ कर चुकी है।

कांग्रेस से सपा में गए

पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव का वर्ष 2014 में एनआरएचएम घोटाले में नाम आने के बावजूद कांग्रेस ने उनको बहराइच से लोकसभा का टिकट दिया था। हालांकि बाद में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और वर्ष 2017 और 2022 में सपा के टिकट पर पयागपुर से चुनाव लड़ा, जिसमें उनको शिकस्त मिली। उनके खिलाफ पूर्व में भी नौ मुकदमे दर्ज रहे हैं।

यूपी में 206 पीपीएस अफसरों का तबादला, लखनऊ में तैनात अफसर भी बदले, तीन पीसीएस के भी ट्रांसफर

(जीएनएस)।

लखनऊ , डीजीपी मुख्यालय ने बृहस्पतिवार को डिप्टी एसपी रैंक के 206 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। लखनऊ में तैनात करीब एक दर्जन डिप्टी एसपी को भी बदला गया है। वहीं, तीन पीसीएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र कुमार को शाहजहांपुर भेजा गया है। लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात विकास कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा भेजा गया है। गोरखपुर में तैनात उदय प्रताप सिंह द्वितीय को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। लखनऊ में तैनात सतीश कुमार राय को मेरठ में पीएसी की छठवीं वाहिनी भेजा गया है।

इसी तरह राजधानी में सहायक पुलिस आयुक्त अभय कुमार मल्ल को बलरामपुर भेजा गया है। महोबा में तैनात गौरव उपाध्याय और अंबेडकरनगर में तैनात शुभम कुमार को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा से वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए राजेश कुमार सिंह को अब लखनऊ कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है।

कासगंज में तैनात शाहिदा नसरीन को भी लखनऊ कमिश्नरेट भेजा गया है। लखनऊ में तैनात शिप्रा पांडेय को डीजीपी मुख्यालय में आईजी कानून-व्यवस्था के कार्यालय में तैनात किया गया है। अनुष्का को लखनऊ से प्रयागराज स्थित पीएसी की चतुर्थ वाहिनी भेजा गया है। सुरेंद्र शर्मा को लखनऊ से बरेली में पीएसी की 8वीं वाहिनी भेजा गया है। वीरेंद्र विक्रम को लखनऊ से कानपुर कमिश्नरेट भेजा गया है। अतुल कुमार पांडेय को रामपुर से लखनऊ कमिश्नरेट भेजा गया है।

अभिषेक कुमार पांडेय को कानपुर कमिश्नरेट से लखनऊ भेजा गया है। विनय कुमार द्विवेदी को लखनऊ से मुजफ्फरनगर भेजा गया है। राजकुमार सिंह द्वितीय को लखनऊ से प्रयागराज कमिश्नरेट भेजा गया है। अनिद्य विक्रम सिंह को लखनऊ से गाजीपुर भेजा गया है। रंजीत कुमार को कानपुर से लखनऊ कमिश्नरेट भेजा गया है। अभिनव यादव द्वितीय को लखनऊ से एटीएस भेजा गया है। प्रतीक दहिया को पीलीभीत से लखनऊ कमिश्नरेट भेजा गया है। महेश त्यागी को नोएडा कमिश्नरेट से लखनऊ कमिश्नरेट भेजा गया है।

तीन पीसीएस अफसरों के तबादले

प्रदेश में तीन पीसीएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए हैं। सृष्टि धवन को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार राय को चित्रकूट धाम मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। आनंद मोहन उपाध्याय को कानपुर नगर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।

राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री मोदी से देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया

(जीएनएस)।

मुंबई, राकांपा (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की जनता ईंधन की बढ़ती कीमतों और एलपीजी सब्सिडी में कटौती जैसी समस्याओं का सामना कर रही है।

सुले ने कहा कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर अर्थशास्त्रियों से सलाह ली जानी चाहिए।

उन्होंने भाजपा पर "दलों को तोड़ने की आदत" होने का आरोप लगाते हुए इस चलन को लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह बताया।

राकांपा (एसपी) नेता ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, "देश सबसे पहले आता है, उसके बाद राज्य, पार्टी और परिवार। अगर देश सुरक्षित रहेगा, तो बाकी सब कुछ भी सुरक्षित रहेगा।"

बारामती की सांसद ने कहा कि विपक्ष 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सरकार के साथ मजबूती से खड़ा था और आर्थिक मुद्दों से निपटने में भी वैसा ही समर्थन देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है।

मौजूदा हालात की तुलना संप्रग सरकार के दौर से करते हुए, राकांपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कच्चे तेल की कीमतें 108-110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, जबकि उस समय डॉलर के मुकाबले रुपया 60-65 के भाव पर था और पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम थीं।

उन्होंने कहा, "आज कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा हैं। जब डॉ. मनमोहन सिंह ने ईंधन की कीमतें दो रुपये बढ़ाई थीं, तो भाजपा ने जबरदस्त हंगामा किया था। अब कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं?"

सुले ने देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान का जिक्र किया और कहा कि सत्ता में 12 साल रहने के बाद भी भाजपा कांग्रेस को ही निशाना बनाती रही है।

जब उनसे प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पर हमले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "अगर मैंने 12 साल काम किया होता, तो मैं अपने काम के बारे में बात करती। 12 साल बाद भी भाजपा को कांग्रेस के बारे में ही बात करनी पड़ती है। यही कांग्रेस की सफलता है।"

शिवसेना (उबाठा) सांसद संजय राउत के इस सुझाव के बारे में पूछे जाने पर कि तृणमूल कांग्रेस और राकांपा (एसपी) को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, सुले ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है।

सुले ने कहा, "मेरे लिए संजय राउत बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन क्या होगा और कैसे होगा, यह तो समय ही बताएगा।"

विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिशें किए जाने का आरोप लगाते हुए सुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), दोनों ही ऐसी स्थितियों का सामना कर चुकी हैं।

उन्होंने कहा, "पहले शिवसेना टूटी और फिर राकांपा। हम इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए, हम तृणमूल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सच को परेशान किया जा सकता है,

भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के हमलों के खिलाफ भारत ने कड़ा विरोध जताया

(जीएनएस)।

भारत ने ओमान के तट पर भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले तीन मालवाहक जहाजों पर हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। ये घटनाएं, जो चार दिनों में हुईं, उनमें तीन भारतीय नागरिकों की

मौत हो गई। भारतीय सरकार ने इस तरह की कार्रवाइयों को तत्काल समाप्त करने की मांग की है।

पहले हमले में 8 जून को पनामा-ध्वजांकित तेल टैंकर मैरीवेक्स शामिल था, जिसे अमेरिकी सेना ने निष्क्रिय कर दिया था। जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। 10 जून को, एक अन्य पनामा-ध्वजांकित टैंकर, सेट्टेबेलो, पर हमला किया गया, जिसमें 24 भारतीय नाविकों में से तीन की मौत हो गई।

लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, सपा मुखिया अखिलेश यादव के पोस्ट को गंभीरता से नहीं लेती जनता

सहकारिता भवन में भाजपा महानगर के विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल

(जीएनएस)। लखनऊ। नरेन्द्र मोदी सरकार में वाणिज्य एवं भारी उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर लखनऊ में गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। गोयल ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पौधारोपण भी किया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट को लेकर कहा कि अखिलेश यादव के ट्वीट को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जिस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को विकास से दूर रखा, अराजकता फैलाई और भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया, वह जनता में अनुकरणीय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पूरे राज्य को बदहाल छोड़ दिया था। बिना किसी विकास व नई फैक्ट्रियों या कानून-व्यवस्था में सुधार के तो जनता उन्हें एक बार फिर नकार देगी। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 'डबल-इंजन सरकार' निश्चित रूप से यूपी की जनता की सेवा के लिए वापस आएगी।

गोयल ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया दावों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने कहा कि उप्र के लोग उनके पोस्ट पर विश्वास नहीं करते। गोयल ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर विकास में बाधा, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति और भेदभाव की राजनीति का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी।

सहकारिता भवन में भाजपा महानगर के विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया। पीयूष गोयल ने कहा कि उनके लिए यह अवसर विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वर्ष 1947 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपना उनके लिए गौरव का विषय है। इसी मंत्रालय की नींव डॉ. मुखर्जी ने रखी थी।

राघव चड्ढा ने खामोशी तोड़ी, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 17 दिनों की लंबी खामोशी के बाद सोशल मीडिया पर फिर सक्रिय हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए एक लंबा ट्वीट किया है। आखिरी बार 23 मई को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। उसके बाद नीट पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर उनकी चुप्पी पर काफी चर्चा हो रही थी।

राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में लिखा कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4,399 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा कर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के

रिकॉर्ड को पार कर गए हैं। उन्होंने इसे भारतीय गणतंत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि बताया।

तीन बार निरंतर विश्वास हासिल करना सामान्य उपलब्धि नहीं: चड्ढा

उन्होंने भारत की विविधता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1.4 अरब लोगों वाले इस देश में 22 अनुसूचित भाषाएं, सैकड़ों बोलियां, कई धर्म, जातियां और समुदाय एक साथ रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था में लगभग 98 करोड़ मतदाताओं के बीच तीन बार (2014, 2019 और 2024) निरंतर विश्वास हासिल करना सामान्य उपलब्धि नहीं है।

राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि नेहरू जी का कार्यकाल एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर था, जबकि मोदी जी ने गठबंधन और क्षेत्रीय दलों के कड़े मुकाबले वाले दौर में लगातार बहुमत हासिल किया है। उन्होंने इसे बेहद कठिन उपलब्धि करार दिया और देशवासियों से इस ऐतिहासिक क्षण पर विचार करने की अपील की।

मोदी सरकार के 12 स्वर्णिम वर्षों पर सांसद रेखा शर्मा का जनसंपर्क अभियान, मोरनी में किया पौधारोपण

पंचकूला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण के 12 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कालका एवं पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों में विशेष जनसंपर्क एवं संवाद अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं, ऐतिहासिक निर्णयों तथा पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना रहा।

अभियान के तहत सांसद रेखा शर्मा ने कालका विधानसभा क्षेत्र के मोरनी में आयोजित 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान में भाग लेकर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश नहीं देता, बल्कि भारतीय संस्कृति में माँ के त्याग, समर्पण और स्नेह के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक भावनात्मक प्रयास भी है। उन्होंने लोगों से अपनी माता के सम्मान में एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

इसके बाद सांसद रेखा शर्मा ने मोरनी क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के सरपंचों, पंचों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों और नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में हुए विकास कार्यों, ऐतिहासिक उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

रेखा शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश ने विकास, सुशासन, पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हर घर जल एवं स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं को देश के विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया।

पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में भी सांसद रेखा शर्मा ने विभिन्न सामाजिक संगठनों, वरिष्ठ नागरिकों, महिला समूहों एवं स्थानीय नागरिकों से संपर्क कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है।

जनसंपर्क अभियान के दौरान नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, निर्णायक कार्यशैली और राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों की सराहना की। उपस्थित लोगों ने विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान में अपना सक्रिय योगदान देने का विश्वास व्यक्त किया।

सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष सेवा, समर्पण, सुशासन, विकास और जनकल्याण की गौरवशाली यात्रा के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भी केंद्र सरकार विकसित भारत के संकल्प को लेकर इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती रहेगी।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला शक्ति, युवा साथी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

'माफ कर दो', डेड बॉडी पर टिप्पणी करने वाली डॉ सेजल को होगी सजा? फूट-फूटकर माफी मांगी

(जीएनएस)।

मुंबई की डॉक्टर सेजल पवार इन दिनों सोशल मीडिया पर भारी विवादों के घेरे में हैं। कॉमेडियन प्रणित मोरे के स्टैंड-अप शो में दर्शकों से इंटरैक्शन के दौरान शवों के निजी अंगों की तुलना वाली उनकी टिप्पणी वायरल होने के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया। शरीर दान करने वालों के प्रति सम्मान, चिकित्सा नैतिकता और कॉमेडी की सीमाओं पर सवाल उठे।

आलोचना बढ़ने पर सेजल ने 11 जून 2026 को वीडियो जारी कर माफी मांगी। ट्रोलिंग से तंग आकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। यह घटना प्रणित मोरे के शो में पहले वायरल हुए '370 रुपये की बिरयानी' विवाद के ठीक बाद आई है, जिससे स्टैंड-अप कॉमेडी और पब्लिक परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी पर फिर बहस छिड़ गई है। आइए विस्तार से जानते हैं अपने माफीनामा में क्या क्या सेजल ने कहा? समन जारी के बाद क्या अब होगी सजा? क्या कहती हैं धाराएं?

क्या कहा था सेजल पवार ने?

शो में ऑडियंस इंटरैक्शन के दौरान प्रणित मोरे ने पूछा कि क्या डॉक्टर शव परीक्षण के दौरान गंभीर रहते हैं या मजाक भी करते हैं। सेजल ने मेडिकल कॉलेज के दिनों का जिक्र करते हुए पुरुष शवों के गुप्तांगों की तुलना वाली टिप्पणी की। क्लिप में वे हंसते हुए यह बात बता रही थीं।

यह क्लिप दो-तीन महीने पुरानी थी, लेकिन 9-10 जून 2026 को वायरल हो गई। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अंग दान करने वालों का अपमान बताया। कई डॉक्टर्स और छात्रों ने कहा कि Cadavers शिक्षा के लिए दान किए जाते हैं, उनका सम्मान बनाए रखना डॉक्टरों की जिम्मेदारी है।

सेजल पवार मुंबई के केईएम (KEM) अस्पताल से जुड़ी डॉक्टर, एमबीबीएस छात्रा हैं। वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और स्टैंड-अप कॉमेडी की शुरूआत कर रही थीं। उनका इंस्टाग्राम पहले सक्रिय था, जहां उन्होंने मेडिकल लाइफ और कॉमेडी क्लिप्स शेयर की थीं। विवाद के बाद उन्होंने प्रोफाइल से कॉलेज का जिक्र हटा लिया और अकाउंट्स बंद कर दिए।

11 जून को जारी वीडियो में सेजल ने भावुक होते हुए कहा कि सभी को नमस्कार... मैंने जो तीन माह पहले शो किया था, उसका एक हिस्सा क्लिप वायरल हो रहा है... मैं बस यहां आना चाहता था और कहना चाहता था कि मुझे माफ कर दीजिए... मैंने बहुत गलत बात कह दी। मुझसे गलती हुई। मैंने ऐसा कभी जानबूझकर नहीं सोचा था...मैं इसके बारे में जस्टिफाई करने नहीं आई हूं। मैं जिम्मेदारी लेती हूं। पीछे मुड़कर देखने पर मैं समझ सकती हूं कि मेरे शब्दों का मतलब मेरे इरादे से अलग कैसे निकाला जा सकता है। यह मेरा पहला स्टैंड-अप शो था... मुझे आइडिया नहीं था कि दो-तीन महीने पुरानी क्लिप आज वायरल हो जाएगी। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कुछ सार्वजनिक रूप से नहीं होगा...यह मेरी गलती है और मुझे माफ करें... अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो सॉरी।'

स्टैंड-अप कॉमेडी शो से जुड़े विवादित कंटेंट को लेकर कॉमेडियन प्रणित मोरे हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कार्रवाई शुरू की है।